PRESS REPORTS

Client : DDMA And NDMA

News Paper : DELHI EXPRSS

Edition : NEW DELHI

Date : 23.12.2011

SPAN

विधायकों ने सीखे आपदा प्रबंधन के गुर

- *दिल्ली सरकार दिल्ली को पूरी तरह आपदा प्रबंधन और इससे निपटने के लिए तैयार बनाने को कृतसंकल्प :श्रीमती दीक्षित*
- *तुरन्त रिस्पोंस प्रणाली मजबूत किए जाने की जरूरत*
- *विधानसभा में कार्यशाला का आयोजन किया गया*
- *विधायकों से आपदा प्रबंधन और एहतियात का संदेश फैलाने का आग्रह*

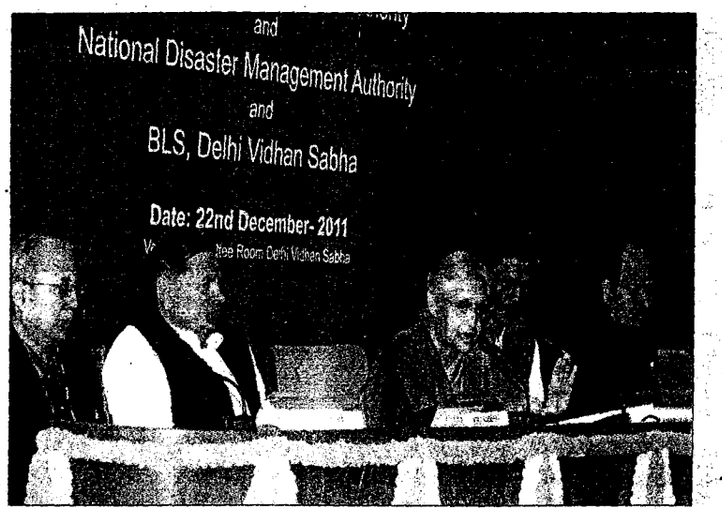

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में गुरूवार को आयोजित आपदा प्रबंधन और इससे निपटने के लिए तैयार बनने के एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्याशाला में दिल्ली के विधायकों ने आपदा प्रबंधन के गुर सीखे। विधायकों के लिए आपदा प्रबंधन संबंधित अभ्यास भी प्रदर्शित किया गया।

कार्यशाला में उपस्थित विधायकों को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली को पूरी तरह आपदा प्रबंधन और इससे निपटने के लिए तैयार रखने को कृतसंकल्प है। जब आपदा आती है तो विनाश लीला होती है जिससे जीवन, रोजगार और सम्पत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचता है। इससे न केवल जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है अपितु पूरी मेहनत से हासिल किए गए विकास के फायदे भी ध्वस्त हो जाते हैं। प्रगति के मामले में देश और शहर कई दशक पिछड़ जाते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री शशिधर रेड्डी, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष डॉ. योगानंद शास्त्री, दिल्ली के राजस्व मंत्री डॉ. अशोक कुमार वालिया, मुख्य सचिव श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी और राजस्व तथा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव श्री विजयदेव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कई मंत्रियों समेत बड़ी संख्या में विधायक कार्यशाला में उपस्थित हुए।

श्रीमती दीक्षित ने कहा कि भूकम्प की दृष्टि से भी दिल्ली पर खतरा मंडराता है क्योंकि ये जोन-4 में आती है। इसके घने बसे इलाकों में असुरक्षित इमारतें हैं जो बिना नक्शे के बनी है। इस वजह से भी खतरा बढ़ता है। पहले रिस्पोंस का मतलब राहत, बचाव और पुनर्निर्माण समझा जाता था लेकिन अब इसके दायरे में आपदा न होने देने के लिए एहतियात और जानमाल के नुकसान को कम से कम करना शामिल है। हमें आपदा के दौरान सुरक्षा की भावना का आभास विकसित करना होगा। इस दिशा में निर्वाचित प्रतिनिधि अहम भूमिका निभा सकते हैं और लोगों का इन मुद्दों पर जागरूक कर सकते हैं। आम आदमियों को यह भी बताया जाना चाहिए कि दहशत फैलाने से नुकसान अधिक होता है। प्रशिक्षण पर बल देते हुए श्रीमती दीक्षित ने कहा कि प्रशिक्षण में एहतियात सुनिश्चित करने और नुकसान कम करने को उजागर किया जाना चाहिए और इसके लिए बच्चों, इंजीनियरों, वास्तुकारों और अन्य सभी सम्बद्ध पक्षों को जानकारी दी जानी जरूरी है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि आपदा में सुरक्षा और बचाव पर जोर देने के लिए इलैक्ट्रोनिक मीडिया और एफएम रेडियो का इस्तेमाल किया जाए।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ योगानंद शास्त्री ने कहा आपदा की समयावधि कम रही है लेकिन इसकी मार सदियों तक सही जाती है। आपदा प्रबंधन में एहतियात और इसके अलावा अपनी तथा दूसरों की जानें बचाना शामिल है। पुराने समय से आपदाओं के वर्णन मिलते हैं। प्राकृतिक आपदा हमेशा विनाशकारी और भयावह होती है। राजस्व मंत्री डॉ. वालिया ने कहा कि आपात स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली चालू करके रिस्पोंस सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए अस्पतालों, एम्बुलेंस और क्लीनिक को उन्नत बनाया जाना और वहां के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। सभी अस्पतालों के बीच तालमेल को भी प्रभावी बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में भूकम्प से सुरक्षा पर जोर दिए जाने की जरूरत है। भूकम्प की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली में ढ़ाई महीने का अभियान शुरू किया जा रहा है जिसमें लोगों में जागरूकता लाई जायेगी। एक मीडिया अभियान भी जल्द शुरू किया जाएगा। दिल्ली में 15 फरवरी, 2012 को बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल होगी। मुख्य सचिव श्री त्रिपाठी ने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों और आम आदमियों को आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए पूरा सहयोग देगी। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री रेड्डी ने अपना प्रमुख भाषण देते हुए कहा कि 2004 में सुनामी आने के बाद इस प्राधिकरण का गठन किया गया।

PRESS REPORTS

Client : DDMA And NDMA

News Paper : MAHA MEDHA

Edition : NEW DELHI

Date : 23.12.2011

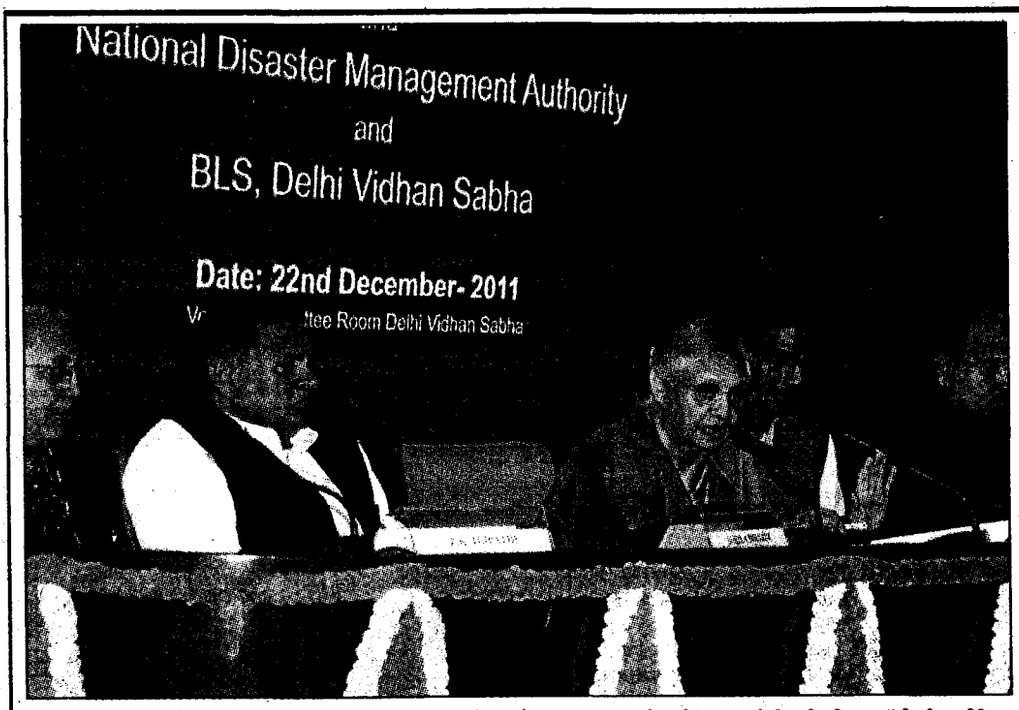

नई दिल्ली : विधायकों के लिए आपदा प्रबंधन पर आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करतीं दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। राजेश भसीन

'आपदा से निपटने को दिल्ली तैयार'

नई दिल्ली (संवाददाता)। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को पूरी तरह आपदा प्रबंधन और इससे निपटने के लिए तैयार रखने को कृतसंकल्प है। जब आपदा आती है तो विनाश लीला होती है जिससे जीवन, रोजगार और सम्पति को व्यापक नुकसान पहुंचता है। इससे न केवल जन-जीवन अस्त-व्यस्त होता है अपितु पूरी मेहनत से हासिल किए गए विकास के फायदे भी ध्वस्त हो जाते हैं। प्रगति के मामले में देश और शहर कई दशक पिछड़ जाते हैं।

श्रीमती दीक्षित ने दिल्ली विधानसभा में विधायकों के लिए आपदा प्रबंधन आयोजित अब तक की पहली कार्यशाला में ये विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शशिधर रेडडी, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष डॉ योगानंद शास्त्री, दिल्ली के राजस्व मंत्री डॉ अशोक कुमार वालिया, मुख्य सचिव प्रवीण कुमार त्रिपाठी और राजस्व तथा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव विजयदेव ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्रीमती दीक्षित ने कहा कि अलग-अलग किस्म की आपदा से सभी लोगों को खतरा बना रहता है। दिल्ली में आपदा की आशंका बनी रहती है क्योंकि बम विस्फोट, आतंकवादी घटनाएं, अग्नि दुर्घटना, इमारतें ढहने और सड़क दुर्घटनाएं आपदा की स्थिति उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा भूकम्प की दृष्टि से भी दिल्ली पर खतरा मंडराता है क्योंकि ये जोन-4 में आती है। इसके घने बसे इलाकों में असुरक्षित इमारतें हैं जो बिना नक्शे के बनी हैं। इस वजह से भी खतरा बढ़ता है। पहले रिस्पोंस का मतलब राहत, बचाव और पुनर्निर्माण समझा जाता था, लेकिन अब इसके दायरे में आपदा न होने देने के लिए एहतियात और जानमाल के नुकसान को कम से कम करना शामिल है। हमें आपदा के दौरान सुरक्षा की भावना का आभास विकसित करना होगा। इस दिशा में निर्वाचित प्रतिनिधि अहम भूमिका निभा सकते हैं और लोगों का इन मुद्दों पर जागरूक कर सकते हैं। आम आदमियों को यह भी बताया जाना चाहिए कि दहशत फैलाने से नुकसान अधिक होता है। प्रशिक्षण पर बल देते हुए श्रीमती दीक्षित ने कहा कि प्रशिक्षण में एहतियात सुनिश्चित करने और नुकसान कम करने को उजागर किया जाना चाहिए और इसके लिए बच्चों, इंजीनियरों, वास्तुकारों और अन्य सभी सम्बद्ध पक्षों को जानकारी दी जानी जरूरी है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि आपदा में सुरक्षा और बचाव पर जोर देने के लिए इलैक्ट्रॉनिक मीडिया और एफएम रेडियो का इस्तेमाल किया जाए।

- **मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने तुरन्त रिस्पांस प्रणाली को मजबूत किए जाने को बताया जरूरी**
- **विधायकों के लिए भूकंप की त्रासदी से निपटने की तैयारी की कार्यशाला विधानसभा में सम्पन्न**
- **विधायकों से आपदा प्रबंधन और एहतियात का संदेश फैलाने का आग्रह**
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने भाषण दिया और दिल्ली को सहयोग देते रहने का आश्वासन दिया**

विस अध्यक्ष डॉ योगानंद शास्त्री ने कहा आपदा की समयावधि कम रही है लेकिन इसकी मार सदियों तक सही जाती है। आपदा प्रबंधन में एहतियात और इसके अलावा अपनी तथा दूसरों की जानें बचाना शामिल है। राजस्व मंत्री डॉ. वालिया ने कहा कि आपात स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली चालू करके रिस्पोंस सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए अस्पतालों, एम्बुलेंस और क्लीनिक को उन्नत बनाया जाना और वहां के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। दिल्ली में 15 फरवरी, 2012 को बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल होगी। मुख्य सचिव त्रिपाठी ने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों और आम आदमियों को आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए पूरा सहयोग देगी। सरकार आपदा प्रबंधन के उपायों पर पूरा जोर दे रही है।

PRESS REPORTS

Client : DDMA And NDMA

News Paper : PANJAB KESARI

Edition : NEW DELHI

Date : 23.12.2011

आपदा प्रबंधन मजबूत बनाया जाएगा

नई दिल्ली, (नगर प्रतिनिधि): दिल्ली में आपदा की आशंका बनी रहती है क्योंकि बम विस्फोट, आतंकवादी घटनाएं, अग्नि दुर्घटना, इमारतें ढहने और सड़क दुर्घटनाएं आपदा की स्थिति उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा भूकम्प की दृष्टि से भी दिल्ली पर खतरा मंडराता रहता है क्योंकि यह जोन-4 में आती है। इसके घने इलाकों में असुरक्षित इमारतें हैं जो बिना नक्शे के बनी हैं, इस वजह से खतरा भी बढ़ता है। दिल्ली सरकार दिल्ली का आपदा प्रबंधन मजबूत बनाने के लिए कृतसंकल्प है। आपदा के दौरान लोगों में सुरक्षा की भावना का आभास विकसित करने की जरूरत है। इस दिशा में निर्वाचित प्रतिनिधि अहम भूमिका निभा सकते हैं। यह बात यहां मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कही। वह दिल्ली विधानसभा में विधायकों के लिए आयोजित आपदा प्रबंधन कार्यशाला में बोल रही थी।

PRESS REPORTS

Client : DDMA And NDMA

News Paper : DESHBANDHU

Edition : NEW DELHI

Date : 23.12.2011

आपदा प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर (देशबन्धु)। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने आज कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को पूरी तरह आपदा प्रबंधन और इससे निपटने के लिए तैयार रखने को कृतसंकल्प है। जब आपदा आती है तो विनाश लीला होती है जिससे जीवन, रोजगार और सम्पत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचता है। इससे न केवल जन-जीवन अस्त-व्यस्त होता है अपितु पूरी मेहनत से हासिल किए गए विकास के फायदे भी ध्वस्त हो जाते हैं। प्रगति के मामले में देश और शहर कई दशक पिछड़ जाते हैं। श्रीमती दीक्षित ने दिल्ली विधानसभा में विधायकों के लिए आपदा प्रबंधन आयोजित अब तक की पहली कार्यशाला में ये विचार व्यक्त किए।

■ **विधायकों के लिए आपदा से निपटने की कार्यशाला तैयार**

उन्होंने राजधानी में बम विस्फोट, आतंकवादी घटनाएं, अग्नि दुर्घटना, इमारतें ढहने और सड़क दुर्घटनाएं आपदा की स्थिति की संभावना रहती हैं। इसके अलावा भूकम्प की दृष्टि से भी दिल्ली पर खतरा मंडराता है क्योंकि ये जोन-4 में आती है। इसके घने बसे इलाकों में असुरक्षित इमारतें हैं जो बिना नक्शे के बनी हैं। इस दिशा में निर्वाचित प्रतिनिधि अहम भूमिका निभा सकते हैं और लोगों का इन मुद्दों पर जागरूक कर सकते हैं। आम आदमियों को यह भी बताया जाना चाहिए कि दहशत फैलाने से नुकसान अधिक होता है। प्रशिक्षण और जागरूकता पर बल देते हुए कहा कि बच्चों, इंजीनियरों, वास्तुकारों और अन्य सभी सम्बद्ध पक्षों को जानकारी दी जानी ज़रूरी है।

दिल्ली सरकार दिल्ली को पूरी तरह आपदा प्रबंधन और इससे निपटने के लिए तैयार बनाने को कृतसंकल्प : शीला

❖ तुरन्त रिस्पोंस प्रणाली मजबूत किए जाने की जरूरत ❖ विधायकों के लिए भूकम्प की त्रासदी से निपटने की तैयारी की कार्यशाला विधानसभा में सम्पन्न ❖ विधायकों से आपदा प्रबंधन और एहतियात का संदेश फैलाने का आग्रह ❖ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने प्रमुख भाषण दिया और दिल्ली को सहयोग देते रहने का आश्वासन दिया

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने आज कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को पूरी तरह आपदा प्रबंधन और इससे निपटने के लिए तैयार रखने को कृतसंकल्प है। जब आपदा आती है तो विनाश लीला होती है जिससे जीवन, रोजगार और सम्पत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचता है। इससे न केवल जन-जीवन अस्त-व्यस्त होता है अपितु पूरी मेहनत से हासिल किए गए विकास के फायदे भी ध्वस्त हो जाते हैं। प्रगति के मामले में देश और शहर कई दशक पिछड़ जाते हैं। श्रीमती दीक्षित ने दिल्ली विधानसभा में विधायकों के लिए आपदा प्रबंधन आयोजित अब तक की पहली कार्यशाला में ये विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री शशिधर रेड्डी, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष डॉ योगानंद शास्त्री, दिल्ली के राजस्व मंत्री डॉ. अशोक कुमार वालिया, मुख्य सचिव श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी और राजस्व तथा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव श्री विजयदेव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कई मंत्रियों समेत बड़ी संख्या में विधायक कार्यशाला में उपस्थित हुए। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित अभ्यास भी प्रदर्शित किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्रीमती दीक्षित ने कहा कि अलग-अलग किस्म की आपदा से सभी लोगों को खतरा बना रहता है। दिल्ली में आपदा की आशंका बनी रहती है क्योंकि बम विस्फोट, आतंकवादी घटनाएं, अग्नि दुर्घटना, इमारतें ढहने और सड़क दुर्घटनाएं आपदा की स्थिति उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा भूकम्प की दृष्टि से भी दिल्ली पर खतरा मंडराता है क्योंकि ये जोन-4 में आती है। इसके घने बसे इलाकों में असुरक्षित इमारतें हैं जो बिना नक्शे के बनी है। इस वजह से भी खतरा बढ़ता है। पहले रिस्पोंस का मतलब राहत, बचाव और पुनर्निर्माण समझा जाता था लेकिन अब इसके दायरे में आपदा न होने देने के लिए एहतियात और जानमाल के नुकसान को कम से कम करना शामिल है। हमें आपदा के दौरान सुरक्षा की भावना का आभास विकसित करना होगा। इस दिशा में निर्वाचित प्रतिनिधि अहम भूमिका निभा सकते हैं और लोगों का इन मुद्दों पर जागरूक कर सकते हैं। आम आदमियों को यह भी बताया जाना चाहिए कि दहशत फैलाने से नुकसान अधिक होता है। प्रशिक्षण पर बल देते हुए श्रीमती दीक्षित ने कहा कि प्रशिक्षण में एहतियात सुनिश्चित करने और नुकसान कम करने को उजागर किया जाना चाहिए और इसके लिए बच्चों, इंजीनियरों, वास्तुकारों और अन्य सभी सम्बद्ध पक्षों को जानकारी दी जानी जरूरी है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि आपदा में सुरक्षा और बचाव पर जोर देने के लिए इलैक्ट्रोनिक मीडिया और एफएम रेडियो का इस्तेमाल किया जाए।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ योगानंद शास्त्री ने कहा आपदा की समयावधि कम रही है लेकिन इसकी मार सदियों तक सही जाती है। आपदा प्रबंधन में एहतियात और इसके अलावा अपनी तथा दूसरों की जानें बचाना शामिल है। पुराने समय से आपदाओं के वर्णन मिलते हैं। प्राकृतिक आपदा हमेशा विनाशकारी और भयावह होती है। राजस्व मंत्री डॉ वालिया ने कहा कि आपात स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली चालू करके रिस्पोंस सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए अस्पतालों, एम्बुलेंस और क्लीनिक को उन्नत बनाया जाना और वहां के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। इससे आपदा के समय जल्द से जल्द मदद और बचाव कार्य किया जा सकेगा। ऐसे कार्य में एक-एक पल कीमती होता है और हड़बड़ में किए गए बचाव कार्य से कई बार ज्यादा नुकसान भी हुआ है। सभी अस्पतालों के बीच तालमेल को भी प्रभावी बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में भूकम्प से सुरक्षा पर जोर दिए जाने की जरूरत है। भूकम्प की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली में ढाई महीने का अभियान शुरू किया जा रहा है जिसमें लोगों में जागरूकता लाई जायेगी। एक मीडिया अभियान भी जल्द शुरू किया जाएगा। दिल्ली में 15 फरवरी, 2012 को बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल होगी। मुख्य सचिव श्री त्रिपाठी ने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों और आम आदमियों को आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए पूरा सहयोग देगी। सरकार आपदा प्रबंधन के उपायों पर पूरा जोर दे रही है। कई भवनों की रिटरो फिटिंग की जा रही है।

राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री रेड्डी ने अपना प्रमुख भाषण देते हुए कहा कि 2004 में सुनामी आने के बाद इस प्राधिकरण का गठन किया गया। दिल्ली में जनसंख्या का घनत्व का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहां आपदा प्रबंधन के कई पहलू अलग हैं इसलिए दिल्ली अन्य राज्यों से इस मामले में कुछ अलग है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आपदा प्रबंधन के बारे में विष्वस्तरीय तैयारी की जाए। असुरक्षित भवनों का उल्लेख करते हुए कहा कि महज पांच प्रतिशत अतिरिक्त लागत से भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। उनके प्राधिकरण ने शहरों में बाढ़ की स्थिति के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसका रिस्पोंस फोर्स काम कर रहा है जिसमें 12 बटालियन हैं। दिल्ली की जरूरतें पूरी करने के लिए एक बटालियन नोएडा में तैनात की गई है। एनडीएमए अपने प्रयास जारी रखेगी कि आपदा में नुकसान कम से कम हो। इस दिशा में एनडीएमए दिल्ली सरकार को पूरा सहयोग देगी।

बालिका छात्रावास में घुसने की कोशिश, फायरिंग की

इंदिरा के जीवन पर आधारित संस्कृत काव्य की पुस्तक का लोकार्पण

दैनिक भास्कर
23 दिसंबर (शुक्रव

आपदा प्रबंधन कार्यशाला को संबोधित करतीं मुख्यमंत्री शीला दीक्षित।

आपदा प्रबंधन को लेकर विधायकों की कार्यशाला

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

आपदा प्रबंधन और इससे निपटने की तैयारी को लेकर दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को विधायकों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को पूरी तरह आपदा प्रबंधन व इससे निपटने के लिए तैयार रखने को कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि जब आपदा आती है तो प्रगति के मामले में देश व शहर कई दशक पिछड़ जाते हैं। दिल्ली में आपदा की आशंका बनी रहती है क्योंकि बम विस्फोट, आतंकवादी घटनाएं, अग्नि दुर्घटना, इमारतें ढहने और सड़क दुर्घटनाएं आपदा की स्थिति पैदा करती हैं। इसके अलावा भूकंप की दृष्टि से भी दिल्ली पर खतरा मंडराता है क्योंकि ये जोन-4 में आती है। पहले रिस्पांस का मतलब राहत, बचाव और पुनर्निर्माण समझा जाता था लेकिन अब इसके दायरे में आपदा न होने देने के लिए एहतियात व जानमाल के नुकसान को कम से कम करना शामिल है।

बजाती हुई एम्बुलेंस आई पुलिस ने जब उन्हें रुकने को कहा तो उन्होंने

अपने रिश्तेदारों
कवो पार्षद

उठाते हुए कूड़ा न उठाए जाने को लेकर अधिकारियों की खिचाई की और सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की मांग की।

दूसरी ओर इसके अतिरिक्त विपक्ष के नेता जयकिशन शर्मा ने जगतपुर गांव के चोरी हुए शौचालय का मुद्दा सदन में रखते हुए कहा कि यह सिर्फ एक शौचालय का मामला नहीं है, बल्कि 713 शौचालय गायब हैं। शौचालयों का गायब होने का जिम्मेदार कौन है, उसकी जांच कर दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 499 के तहत दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाए।

का प्रतिनिधिमंडल
ी से मिला

लोग अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं परन्तु आज तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में बंजारा समाज की संख्या 55 से 60 लाख है और पूर्व में कांग्रेस के इतिहास में ही भी नायक व सुधाकर नायक अपने मंत्री पद की जिम्मेदारी बाखूबी निभा चुके हैं परन्तु इस समय बंजारा पिछले दो विधानसभा चुनावों में बंजारा समाज के एक भी प्रतिनिधि को टिकट नहीं दिया गया। पीरगढ़ी

से बरामद पेटियां सहित कार जब्त कर ली व आगे कार्यवाही में जुटी थी।

आपदा प्रबंधन मजबूत बनाया जाएगा

नई दिल्ली (नगर प्रतिनिधि): दिल्ली में आपदा की आशंका बनी रहती है क्योंकि बम विस्फोट, आतंकवादी घटनाएं, अग्नि दुर्घटना, इमारतें ढहने और सड़क दुर्घटनाएं आपदा की स्थिति उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा भूकम्प की दृष्टि से भी दिल्ली पर खतरा मंडराता रहता है क्योंकि यह जोन-4 में आती है। इसके घने इलाकों में असुरक्षित इमारतें हैं जो बिना नक्शे के बनी हैं, इस वजह से खतरा भी बढ़ता है। दिल्ली सरकार दिल्ली का आपदा प्रबंधन मजबूत बनाने के लिए कृतसंकल्प है। आपदा के दौरान लोगों में सुरक्षा की भावना का आभास विकसित करने की जरूरत है। इस दिशा में निर्वाचित प्रतिनिधि अहम भूमिका निभा सकते हैं। यह बात यहां मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कही। वह दिल्ली विधानसभा में विधायकों के लिए आयोजित आपदा प्रबंधन कार्यशाला में बोल रही थी।

ओबीसी के लिए सरकारी प्रयासों की सराहना

नई दिल्ली (सं): आल इंडिया फेडरेशन आफ ओबीसी एम्प्लायज वेलफेयर एसोसिएशन ने ओबीसी के लिए संसदीय समिति गठित करने के लिए प्रस्ताव लाने और सर्वसम्मति से स्वीकार कर लेने के लिए यूपीए सरकार के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया है। उल्लेखनीय, एसोसिएशन की तरफ ओबीसी के लिए कमेटी गठित कर ओबीसी कर्मचारियों और छात्रों की मांगों को पूरा करने के साथ-साथ आरक्षण नीति को लागू करने पर भी निगरानी रखी जा सकेगी। एसोसिएशन के महासचिव ने दलगत भावना से ऊपर उठकर लोगों समस्याओं से जुड़ित उनकी मांग को साकार रूप देने में सहयोग करने के लिए सांसदों का आभार जताया।

73 कालोनियां का आवंटन [illegible] निर्धारित अवधि के भीतर अपना जवाब देने

अपराधों में शामिल
की कला सिखा

नई दिल्ली (स.मेटे) : अपराध तथा अपराधियों से निबटने के बदलते कानून का [illegible] प्रयोग करते समय सख्त लहजा के लिए विख्यात [illegible] जाफरबाद स्थित वेलकम पुलिस स्टेशन का नजारा आला पूरी तरह से बदला [illegible] नजर आ रहा था। यह दृश्य अपराधों में लिप्त रहे लोगों के जीवन में परिवर्तन की दृष्टि से [illegible] पुलिस उपायुक्त संजय जैन द्वारा आर्ट आफ लिविंग के सहयोग से यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत चलाये जा रहे शिविर के समापन के अवसर पर नजर आया। उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस तथा आर्ट आफ लिविंग के कार्यकर्ताओं द्वारा वेलकम पुलिस स्टेशन में 16 दिसम्बर से अपराधों में लिप्त रहे लोगों के कल्याण व परिवर्तन की दृष्टि से शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में उन लोगों को जीवन क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है [illegible] विषय का लक्ष्य कराया [illegible] के माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया था। [illegible] कार्यक्रम में उपस्थित लोगों [illegible]

पहचान

आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार संवेदनशील : शीला

रोसख संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार शहर में पूरी तरह आपदा प्रबंधन और इससे निपटने के लिए तैयार रखने को कृतसंकल्प है। जब आपदा आती है तो विनाश लीला होती है जिससे जीवन, रोजगार और सम्पत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचता है। इससे न केवल जन–जीवन अस्त–व्यस्त होता है बल्कि पूरी मेहनत से हासिल किए गए विकास के फायदे भी ध्वस्त हो जाते हैं। प्रगति के मामले में देश और शहर कई दशक पिछड़ जाते हैं। शीला दीक्षित ने दिल्ली विधानसभा में विधायकों के लिए आपदा प्रबंधन आयोजित अब तक की पहली कार्यशाला में यह विचार व्यक्त किए। इस मौके पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शशिधर रेड्डी, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष डॉ. योगानंद शास्त्री, दिल्ली के राजस्व मंत्री डॉ. अशोक कुमार वालिया, मुख्य सचिव प्रवीण कुमार त्रिपाठी और राजस्व तथा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव विजयदेव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कई मंत्रियों समेत बड़ी संख्या में विधायक कार्यशाला में उपस्थित हुए। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित अभ्यास भी प्रदर्शित किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए शीला दीक्षित ने कहा कि अलग–अलग किस्म की आपदा से सभी लोगों को खतरा बना रहता है। दिल्ली में आपदा की आशंका बनी रहती है क्योंकि बम विस्फोट, आतंकवादी घटनाएं, अग्नि दुर्घटना,

जब आपदा आती है तो विनाश लीला होती है जिससे जीवन, रोजगार और सम्पत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचता है

इमारतें ढहने और सड़क दुर्घटनाएं आपदा की स्थिति उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा भूकम्प की दृष्टि से भी दिल्ली पर खतरा मंडराता है क्योंकि ये जोन–4 में आती है। इसके घने बस इलाकों में असुरक्षित इमारतें हैं जो बिना नक्शे के बनी है। इस वजह से भी खतरा बढ़ता है। पहले रिस्पोंस का मतलब राहत, बचाव और पुनर्निर्माण समझा जाता था लेकिन अब इसके दायरे में आपदा न होने देने के लिए एहतियात और जानमाल के नुकसान को कम से कम करना शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें आपदा के दौरान सुरक्षा की भावना का आभास विकसित करना होगा। इस दिशा में निर्वाचित प्रतिनिधि अहम भूमिका निभा सकते हैं और लोगों का इन मुद्दों पर जागरूक कर सकते हैं। आम आदमियों को यह भी बताया जाना चाहिए कि दहशत फैलाने से नुकसान अधिक होता है। प्रशिक्षण पर बल देते हुए श्रीमती दीक्षित ने कहा कि प्रशिक्षण में एहतियात सुनिश्चित करने और नुकसान कम करने को उजागर किया जाना चाहिए और इसके लिए बच्चों, इंजीनियरों, बास्तुकारों और अन्य सभी सम्बद्ध पक्षों को जानकारी दी जानी जरूरी है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि आपदा में सुरक्षा और बचाव पर जोर देने के लिए इलैक्ट्रोनिक मीडिया और एफएम रेडियो का इस्तेमाल किया जाए।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. योगानन्द शास्त्री ने कहा आपदा की समयावधि कम रही है लेकिन इसकी मार सदियों तक सही जाती है। आपदा प्रबंधन में एहतियात और इसके अलावा अपनी तथा दूसरों की जान बचाना शामिल है। पुराने समय से आपदाओं के वर्णन मिलते हैं। प्राकृतिक आपदा हमेशा विनाशकारी और भयावह होती है। राजस्व मंत्री डॉ. वालिया ने कहा कि आपात स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली चालू करके रिस्पोंस सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए अस्पतालों, एम्बुलेंस और क्लीनिक को उन्नत बनाया जाना और वहां के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। इससे आपदा के समय जल्द से जल्द मदद और बचाव कार्य किया जा सकेगा। ऐसे कार्य में एक–एक पल कीमती होता है और हड़बड़ में किए गए बचाव कार्य से कई बार ज्यादा नुकसान भी हुआ है। सभी अस्पतालों के बीच तालमेल को भी प्रभावी बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में भूकम्प से सुरक्षा पर जोर दिए जाने की जरूरत है। भूकम्प की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली में ढाई महीने का अभियान शुरू किया जा रहा है जिसमें लोगों में जागरूकता लाई जायेगी। एक मीडिया अभियान भी जल्द शुरू किया जाएगा। दिल्ली में 15 फरवरी, 2012 को बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल होगी। मुख्य सचिव श्री त्रिपाठी ने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों और आम आदमियों को आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए पूरा सहयोग देगी। सरकार आपदा प्रबंधन के उपायों पर पूरा जोर दे रही है। कई भवनों की रिटरो फिटिंग की जा रही है।

राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रेड्डी ने अपना प्रमुख भाषण देते हुए कहा कि 2004 में सुनामी आने के बाद इस प्राधिकरण का गठन किया गया। दिल्ली में जनसंख्या का घनत्व का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहां आपदा प्रबंधन के कई पहलू अलग हैं इसलिए दिल्ली अन्य राज्यों से इस मामले में कुछ अलग है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आपदा प्रबंधन के बारे में विश्वस्तरीय तैयारी की जाए। असुरक्षित भवनों का उल्लेख करते हुए कहा कि महज पांच प्रतिशत अतिरिक्त लागत से भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। उनके प्राधिकरण ने शहरों में बाढ़ की स्थिति के बारे में दिशा–निर्देश जारी किए हैं। इसका रिस्पोंस फोर्स काम कर रहा है जिसमें 12 बटालियन हैं। दिल्ली की जरूरत पूरी करने के लिए एक बटालियन नोएडा में तैनात की गई है। एनडीएमए अपने प्रयास जारी रखेगी कि आपदा में नुकसान कम से कम हो। इस दिशा में एनडीएमए दिल्ली सरकार को पूरा सहयोग देगी।

राजकीय स्कूल के बच्चों को नहीं पता कौन थे गांधी

योगेन्द्र तोमर

नई दिल्ली। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यायलय की छात्राएं इस जानकारी से पूरी तरह अनजान है कि महात्मा गांधी कौन थे? और उन्होंने देश के लिए क्या किया था?

राजघाट स्थित महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल पर एक दिवसीय टूर के दौरान बच्चे अपने शिक्षकों के साथ घूमने कि लिए आए थे। जहा उन्होंने सुनहरी धुप में बैठकर पिकनिक का भी आनन्द उठाया। बच्चों के साथ उनके शिक्षक व शिक्षिकाएं भी आये हुए थे लेकिन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जहांगीर पुरी की छात्राओं प्रियंका, [illegible] व [illegible] से उनके इस टूर के बारे में पूछ जाने पर उन्होंने कुछ और ही जवाब दिए। उन्होंने बताया कि उन्हें महात्मा गांधी की समाधि स्थल तक नहीं ले जाया गया तथा गांधी जी के बारे में शिक्षिकाओं द्वारा कोई जानकारी भी नहीं दी गई। हमें नही बताया गया है कि गांधी जी कौन थे और उन्होंने देश के लिए ऐसा क्या किया जो कि इतने प्रसिद्ध हो गये। ये सभी छात्राएं वर्ग छह की है। ये जवाब सरकारी स्कूलों में दी जा रही शिक्षा पर बड़ा सवाल खड़े करते है। क्या सरकार द्वारा प्रति वर्ग शिक्षा पर खर्च की जा रही करोड़ो रुपये कि धन राशि का इसी रूप में परिणाम देश के सामने आने वाला है? सरकारी स्कूल के बच्चों को टूर पर ले जाने कि खानापूर्ती तो सरकारी स्कूल के शिक्षक करते है लेकिन उन्हें जहा टूर पे ले जाया जा रहा है उसके बारे में बच्चों को बताना भी शिक्षक जरूरी नहीं समझते। जबकि टूर पे ले जाने का मकसद सैर–सपाटे के अलावा उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी देना है। बच्चों के साथ आयी शिक्षिकाओं ने सफाई देते हुए कहा कि बच्चों को गांधी जी के बारे में बताया गया था, वे भूल गये होंगे।

शीला दीक्षित ने आपदा प्रबंधन पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष योगानंद शास्त्री के अलावा दिल्ली के विधायक भी मौजूद थे।

विद्यार्थियों का ध्यान अपनी मंजिल की

गुरुद्वारे के लंगर को लाइसेंस की जरूरत नहीं

रोसख ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली

निगम की सत्ता से बेदखल होगी भाजपा : अग्रवाल

सीएम ने किया निहाल विहार में इंट[illegible] बिछाने के कार्य का उद्घाटन

रोसख ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में अपना वजूद खो चु[illegible] पुराना अस्तित्व लौटाने की उम्मीद के साथ दिल्ली जल [illegible] इंटरसेप्टर बिछाने का कार्य शुरू कर दिया है। दिल्ली [illegible] विधानसभा क्षेत्र के निहाल विहार इलाके में मुख्यमंत्री शीला [illegible] इंटरसेप्टर बिछाने के कार्य का गुरुवार को उद्घाटन किया। [illegible] स्थानीय विधायक डॉ. विजेन्द्र सिंह, दिल्ली जल बोर्ड के सीई[illegible] और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा गण्यमान्य लोग मौजूद थे।

इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनव[illegible] सावधानीपूर्वक एक ऐसी योजना बनाई जिससे स्वच्छ यमुना का [illegible] किया जा सके। इसे योजना आयोग के साथ परामर्श से अंति[illegible] गया है। 1978 करोड़ रूपए की इस परियोजना को लागू [illegible] इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड को परियोजना प्रबन्धन परामर्शदात[illegible] है। इस लागत में 11 वर्ष का परिचालन और इन्टरसेप्टर की [illegible] का रखरखाव और फूंजीगत लागत शामिल है। उम्मीद है वि[illegible] प्रमुख नाले और नदी दोनो प्रदूषण रहित हो जाएंगे और नदी [illegible] गुणवत्ता में सुधार होगा जो 41 पीपीएम से कम होकर 12 पीपी[illegible] जाएगी। उपचारित जल का इस्तेमाल पीने के अलावा कार्यों [illegible] जायेगा। इतना ही नहीं उन इलाकों की पानी की गन्दगी को [illegible] सकेगा जहां सीवर लाइन बिछी नहीं है।

शीला दीक्षित ने कहा कि इससे वजीराबाद से ओखला [illegible] किलोमीटर क्षेत्र में नदी की जल की गुणवत्ता में काफी सुधार [illegible] गुणवत्ता वांछित मानक से बहुत नीचे है। इसके कई कारण है [illegible] कचरे और गन्दगी को नदी में डालना, बिना उपचारित गन्दा[illegible] आना, औद्योगिक कचरा नदी में मिल जाना, प्लास्टिक, पॉलीथि[illegible] तत्वों को नदी में बहाया जाना प्रमुख रूप से शामिल है।

श्रीमती दीक्षित ने इस मौके पर सभी दिल्लीवासियों को [illegible] कहा कि इन्टरसेप्टर सीवर बिछाने के काम की शुरुआत से एक [illegible] किरण सामने आई है जिससे नदी का स्वच्छ, निर्मल और आक[illegible] तट का हरा–भरा बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि [illegible] अन्तर्गत सभी पक्षों को तालमेल से काम करना चाहिए और [illegible] करना चाहिए कि उन्हें जो दायित्व मिले हैं उन्हें समय पर पूरा [illegible] दिल्ली नगर निगम नालों और नदी में गन्दगी नहीं फेंकने की [illegible] और गाद निकालेगा तथा बाढ़ लगायेगा। सिंचाई और बाढ़ नि[illegible] भी अपने क्षेत्र में गाद निकालने और बाढ़ निकालने का काम [illegible] से भी नदी तट को कब्जा करने वालों से मुक्त बनाए रखने [illegible] है जबकि डीएसएसआईडीसी अपने सीपीईटी के जरिए औद्योगि[illegible] उपचारित होने के बाद नदी के प्रवाह में जाने देगा। दिल्ली प्र[illegible] समिति नदी के जल की गुणवत्ता के मानदण्डों पर निगरानी रख[illegible] दीक्षित ने इस परियोजना को अत्यन्त लाभकारी बताया जिससे न[illegible] नालों को गैर उपचारित गन्दगी से बचाया जायेगा और अनधिकृ[illegible] तथा बिना सीवर वाले क्षेत्रों, गावों और झुग्गी–झोपडी वाले सीवे[illegible] नालों और नदी में जाने से पहले रोका जायेगा। नजफगढ़, स[illegible] शाहदरा नालों से नदी में 75 प्रतिशत प्रदूषण होता है। नए [illegible] प्लांट तभी लगाए जाएंगे जब मौजूदा का पूरा इस्तेमाल होगा। [illegible] समयबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए 3 अलग–अलग एजें[illegible] सौंपा गया है। तीन प्रमुख नालों के साथ 59 किलोमीटर ल[illegible] से 60 फुट गहरा सीवर जिसका अर्ध व्यास 600 मिलीमी[illegible] मिलीमीटर के बीच बिछाया जायेगा जिससे छोटे नालों से [illegible] गन्दगी को रोका जा सकेगा। इस गन्दगी को संकलन निकट[illegible] में उपचारित किया जायेगा। श्रीमती दीक्षित ने कहा कि अग[illegible] में ऐसा सपना साकार होने वाला है।

आज का राशिफल

मेष – व्यावसायिक क्षेत्र में [illegible] करना पड़ सकता है। सहयोग [illegible] रहेंगे। वाणी की सौम्यता आपको व्यर्थ से बचा सकती है। खान पान में संय[illegible] आवश्यकता है।

वृष:– प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता [illegible] आय और व्यय में संतुलन बना कर [illegible] गया परिश्रम सार्थक होगा। धन लाभ [illegible] नए अनुबंध प्राप्त होंगे। मन प्रसन्न [illegible] महत्वपूर्ण निर्णय न लें।

मिथुन:– जीवनसाथी का सहयोग [illegible]

cmyk

नई दिल्ली, शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2011

एनसीआर

सपा की महानगर और जिला कमेटी के मतभेद सतह पर

गाजियाबाद : विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के पहले ही सपा की महानगर और जिला कमेटी के मतभेद सामने आने लगे हैं। एक प्रत्याशी ने बताया कि जब से जिला और महानगर सपा कमेटी का गठन हुआ है, तभी से श्रेय लेने की होड़ में एक दूसरे की खिंचाई करने में जुटे हैं। चर्चा है कि नई कार्यकारिणी में पुराने और वरिष्ठ नेताओं को हाशिए पर रखा गया है। यह बात बृहस्पतिवार को जिला कार्यकारिणी घोषित होते समय संवाददाता सम्मेलन में चर्चा का विषय रही। हालांकि जिलाध्यक्ष राशिद मलिक ने सफाई दी कि कार्यकर्ता अधिक हो जाने से स्थान की कमी हो जाती है।

एक्शन इ

आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार संवेदनशील : शीला

नई दिल्ली (एआई.सं.) : दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार शहर में पूरी तरह आपदा प्रबंधन और इससे निपटने के लिए तैयार रखने को कृतसंकल्प है। जब आपदा आती है तो विनाश लीला होती है जिससे जीवन, रोजगार और सम्पत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचता है। इससे न केवल जन-जीवन अस्त-व्यस्त होता है बल्कि पूरी मेहनत से हासिल किए गए विकास के फायदे भी ध्वस्त हो जाते हैं। प्रगति के मामले में देश और शहर कई दशक पिछड़ जाते हैं। शीला दीक्षित ने दिल्ली विधानसभा में विधायकों के लिए आपदा प्रबंधन आयोजित अब तक की पहली कार्यशाला में यह विचार व्यक्त किए। इस मौके पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शशिधर रेड्डी, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष डॉ. योगानंद शास्त्री, दिल्ली के राजस्व मंत्री डॉ. अशोक कुमार वालिया, मुख्य सचिव प्रवीण कुमार त्रिपाठी और राजस्व तथा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव विजयदेव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कई मंत्रियों समेत बड़ी संख्या में विधायक कार्यशाला में उपस्थित हुए। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित अभ्यास भी प्रदर्शित किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए शीला दीक्षित ने कहा कि अलग-अलग किस्म की आपदा से सभी लोगों को खतरा बना रहता है। दिल्ली में आपदा की आशंका बनी रहती है क्योंकि बम विस्फोट, आतंकवादी घटनाएं, अग्नि दुर्घटना, इमारतें ढहने और सड़क दुर्घटनाएं आपदा की स्थिति उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा भूकम्प की दृष्टि से भी दिल्ली पर खतरा मंडराता है क्योंकि ये जोन-4 में आती है। इसके घने बसे इलाकों में असुरक्षित इमारतें हैं जो बिना नक्शे के बनी हैं। इस वजह से भी खतरा बढ़ता है। पहले विपदा का मतलब राहत, बचाव और पुनर्निर्माण समझा जाता था लेकिन अब इसके बारे में आपदा न होने देने के लिए एहतियात और जानमाल के नुकसान को कम से कम करना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें आपदा के दौरान सुरक्षा की भावना का आभास विकसित करना होगा। इस दिशा में [illegible] प्रतिनिधि अहम भूमिका निभा सकते हैं और लोगों का इस मुद्दे पर [illegible] कर सकते हैं। आम आदमियों

को यह भी बताया जाना चाहिए कि दहशत फैलाने से नुकसान अधिक होता है। प्रशिक्षण पर बल देते हुए श्रीमती दीक्षित ने कहा कि प्रशिक्षण में एहतियात सुनिश्चित करने और नुकसान कम करने को उजागर किया जाना चाहिए और इसके लिए बच्चों, इंजीनियरों, वास्तुकारों और अन्य सभी सम्बद्ध पक्षों को जानकारी दी जानी जरूरी है।

उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि आपदा में सुरक्षा और बचाव पर जोर देने के लिए इलैक्ट्रोनिक मीडिया और एफएम रेडियो का इस्तेमाल किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. योगानंद शास्त्री ने कहा आपदा की समयावधि कम रही है लेकिन इसकी मार सदियों तक सही जाती है। आपदा प्रबंधन में एहतियात और इसके अलावा अपनी तथा दूसरों की जानें बचाना शामिल है। पुराने समय से आपदाओं के वर्णन मिलते हैं। प्राकृतिक आपदा हमेशा विनाशकारी और भयावह होती है। राजस्व मंत्री डॉ .वालिया ने कहा कि आपात स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली चालू करके रिस्पांस सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए अस्पतालों, एम्बुलेंस और क्लीनिक को उन्नत बनाया जाना और वहां के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। इससे आपदा के समय जल्द से जल्द मदद और बचाव कार्य किया जा सकेगा। ऐसे कार्य में एक-एक पल कीमती होता है और हड़बड़ में किए गए बचाव कार्य से कई बार ज्यादा नुकसान भी हुआ है। सभी अस्पतालों के बीच तालमेल को भी प्रभावी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भूकम्प से सुरक्षा पर जोर दिए जाने की जरूरत है। भूकम्प की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली में ढ़ाई महीने का अभियान शुरू किया जा रहा है जिसमें लोगों में जागरूकता लाई जायेगी। एक मीडिया अभियान भी जल्द शुरू किया जाएगा। दिल्ली में 15 फरवरी, 2012 को बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल होगी। मुख्य सचिव श्री त्रिपाठी ने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों और आम आदमियों को आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए पूरा सहयोग देगी।

सरकार आपदा प्रबंधन के उपायों पर पूरा जोर दे रही है। कई भवनों की रिटरो फिटिंग की जा रही है। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रेड्डी ने अपना प्रमुख भाषण देते हुए कहा कि 2004 में सुनामी आने के बाद इस प्राधिकरण का गठन किया गया। दिल्ली में जनसंख्या का घनत्व का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहां आपदा प्रबंधन के कई पहलू अलग हैं इसलिए दिल्ली अन्य राज्यों से इस मामले में कुछ अलग है।

प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आपदा प्रबंधन के बारे में विश्वस्तरीय तैयारी की जाए। असुरक्षित भवनों का उल्लेख करते हुए कहा कि महज पांच प्रतिशत अतिरिक्त लागत से भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। उनके प्राधिकरण ने शहरों में बाढ़ की स्थिति के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसका रिस्पांस फोर्स काम कर रहा है जिसमें 12 बटालियन हैं। दिल्ली की जरूरतें पूरी करने के लिए एक बटालियन नोएडा में तैनात की गई है। एनडीएमए अपने प्रयास जारी रखेगी कि आपदा में नुकसान कम से कम हो। इस दिशा में एनडीएमए दिल्ली सरकार को पूरा सहयोग देगी।

न्यू

केंद्र स
दोहरा

नई दिल्ल
सरकार व
प्रदेश विभ
का आरोप
मंत्रालय ने
कि विभाउ
जुटाये जा
दिल्ली सर
में नहीं मां
गृह मंत्राल
कि दिल्ली
प्रस्तावित
जाएगा। इर
तथा ऋण
उन्होंने कह
यह भी तय
वित्तीय बोझ
किया जाए
कर्मियों की
बढ़ोत्तरी के
इसके अति
व्यवस्था में
कि केन्द्र स
किया कि
प्रशासनिक
का प्रस्ताव
केन्द्र सरका

सेंधमारी की सेंचुरी ठोंकने

सपा की नई जिला